सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाना

2085. **चौधरी हरि सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गंभीर आर्थिक संकटों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस वजह से कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गेट अल्वा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Appointment cases pending in Public Enterprises Selection Board

2086. SHRI VIREN J. SHAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of cases for appointment pending for consultation before the Public Enterprises Selection Board as on 31st Dec. 1992;

(b) the number of cases in which appointments have been made in consultation with the P.E.S. Board during the year 1992-93; and

(c) the number of cases where appointments have so far been made without the consultation of the P.E.S. Board during the year 1992-93 and the reasons therefor in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) As per available information, there were 16 cases for appointment pending for consultation before the Public Enterprises Selection Board as on 31-12-1992.

(b) Approval for appointment in respect of 153 posts were issued in consultation with PESB during the period 1-4-1992 to 28-2-1993.

(c) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

भ्रष्टाचार के लंबित मामले

2087. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में भ्रष्टाचार के वर्षवार कितने-कितने मामलों का पता लगाया गया ;

(ख) कितने मामले न्यायालयों में पेश किए गए हैं; और

(ग) 31-3-1993 तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में भ्रष्टाचार के कितने-कितने मामले न्यायालयों में पेश किए जाने शेष थे और ये कब से लंबित हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गेट अल्वा) : (क) से (ग) भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। सक्षम प्राधिकारी होने के नाते

संबंधित राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों का शासित करने वाली सेवा शर्तों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई करती है। राज्यों के कार्यों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के बारे में भी, संबंधित राज्य सरकारें कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। नियमों की उपर्युक्त स्थिति का ध्यान में रखते हुए, राज्यों में भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में सूचना भारत सरकार द्वारा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

Increase in the Reservation for Disabled Persons

@2088. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to increase the percentage of reservation for the disabled persons in Government employment; and

(b) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Features of the Annual Plan 1992-93 for the State of Gujarat

2089. SHRI ANANTRAY DEVESHANKER DAVE: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what are the broad features of the annual plan 1992-93 for Gujarat indicating its proposed outlay and the outlay granted; and

(b) what is the industrial and agricultural growth rates contemplated thereunder?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) An outlay of Rs. 1875 crore was agreed between the Government of Gujarat and the Planning Commission for the Annual Plan 1992-93 of Gujarat against an outlay of Rs. 1783 crore proposed by the State Government. Full details of the Annual Plan 1992-93 of Gujarat are available in the Annual Plan 1992-93 document of the State which has been placed in the Parliament Library. However, a Statement indicating the break-up of the approved outlay by major heads of development for the Annual Plan 1992-93 of Gujarat is enclosed. (See below)

(b) No specific growth rates have been contemplated for the Industrial and Agricultural Sectors in the Annual Plan 1992-93 by the Government of Gujarat.

20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2090. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौकरशाही के हस्तक्षेप के कारण 20 सूत्री कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) 20-सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु नौकरशाही को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

@Previously Unstarred Question 1522, transferred from 5th March, 1993.